संख्या: 16 /2024/ 2203/तीस-1-2024

प्रेषक,

राम गोपाल सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2024

विषय: जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-148बी/डीए/पूर्व/21-25/जेईटी/वि0/20-21, दिनांक 08.02.2021 एवं अद्यतन पत्र संख्या-1305बी/डीए/पूर्व/23-25/जेईटी/वि0/20-21, दिनांक 15.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नामित कार्यदायी संस्था से धनराशि रू0 929.60 लाख की लागत का प्रारम्भिक आगणन प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रारम्भिक आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 785.32 लाख प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु आंकलित की गयी । उक्त निर्माण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रश्नगत परियोजना के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के पत्र दिनांक 15.07.2022 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-21/2022/154/तीस-1-2021, दिनांक 31.03.2022 द्वारा आंकलित लागत रू0 785.32 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 140.00 लाख अवमुक्त की गयी थी, जो आहरित नहीं की जा सकी। अत: उक्त शासनादेश दिनांक- 31/03/2022 निरस्त समझा जाये।

3- अत: प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त पत्र दिनांक 15.09.2023 द्वारा जनपद चित्रकूट में डिपो कार्यशाला एवं आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-21/2022/154/तीस-1-2021, दिनांक 31.03.2022 को निरस्त करते हुये वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 785.32 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 392.66 लाख (रू0 तीन करोड़ बानवे लाख छयासठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के साथ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(10) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किया जाये, जिसका दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(11) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

(13) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।

(14) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन के क्रम में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का भी अनुपालन किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-E-9-642-X-2023-24- दिनांक: 15-03-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या: 16 /2024/2203(1)/तीस-1-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी (बजट आवंटन)/ परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-
राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।